प्रेस विज्ञप्ति

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढीकरण के लिए कार्यशाला

अजमेर दिनांक 4 मार्चे 2017, जन स्वास्थ्य अभियान राजस्थान, एनएफआई एवं प्रयास संस्था, चित्तौड़गढ के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृीढीकरण हेतू समुदाय आधारित संगठनों की कार्यशाला एवं पत्रकार वार्ता का आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर में किया गया जिसमें अजमेर एवं नागौर जिले से गैर सरकारी संगठनो के प्रतिनिधियों एवं स्थानीय संवाददाताओं सहित 45 व्यक्तियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. नरेन्द्र गुप्ता संयोजक जन स्वास्थ्य अभियान राजस्थान एवं सलाहकार प्रयास ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढीकरण के लिये स्वयंसेवी संगठनों के योगदान पर विस्तृत चर्चा की और कहा कि संविधान में जिने का अधिकार दिया है तो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा का अधिकार भी इसमें निहित है। देश के समस्त नागरिकों को सामान्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सकल घरेलु उत्पाद का 5 प्रतिशत खर्च करना है किन्तु इसके विपरित सरकार मात्र 1.2 प्रतिशत ही खर्च रही है। देश में कुछ व्यक्ति आवश्यकता से अधिक सम्पन्न है किन्तु ज्यादातर व्यक्तियों के पास नाम मात्र की संपति और संसाधन है इस प्रकार की असमानता से देश में विकट स्थिति बनी हुई हैं। देश में पोषण की पूर्ति के लिये मिड–डे मिल, पूरक पोषहार, राशन की दुकानों के माध्यम से पूर्ति करने की कोशिश की जारी है फिर भी देश में आधे से अधिक महिलाएं एवं बच्चे कुपोषित है। अजमेर एवं नागौर को भूख रहित, कुपोषण मुक्त जिला बनाने के लिये और अधिक काम करने की आवश्यकता है। डॉ. गुप्ता ने निशुल्क दवा एवं जांच योजना पर विस्तृत्व वक्तव्य देते हुए कहा कि भारत में निर्मित जैनेरिक दवाइयों का विश्व के 200 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता हैं। साथ ही उन्होने बताया कि जैनेरिक एवं ब्राण्डेड दवाओं की गुणवत्ता में कोई अन्तर नहीं है। सरकार का दवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए 2 लाख रू. का बजट है, जो कि बहुत अल्पतम हैं। अभी भी 80 व्यक्तियों को उपचार के लिए होने वाला व्यय जेब से करना पड़ रहा है उसमें से भी 70 प्रतिशत व्यक्तियों का पैसा केवल दवाईयों पर खर्च होता है। शुरूआत में इस योजना का संचालन 80 प्रतिशत ठीक हो रहा था लेकिन अब घट कर 60 प्रतिशत से कम हो गया है। इसका कारण कि जिस प्रकार से संचालन होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है, इसके लिए समुदाय के निगरानी की आवश्यकता है। चिकित्सक व अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाता भी दवा कम्पनियों के लालच में आकर भ्रामक बयान दे रहे हैं। इस कारण भी उपभोक्ता भ्रमित हो रहा है। इसके अलावा जो खबरें दवाइयों के सेम्पल फेल होने के आते हैं, यह सब दवाईयों के उचित रख–रखाव व वातावरण नहीं मिल पाने के कारण होता है। अतः हमें जागरूक होने की आवश्यकता हैं। डॉ. गुप्ता ने बताया कि हृदय रोग के उपचार में लगाये जाने वाले कार्डियक स्टेण्टस का मूल्य निर्धारित होगा। भारत सरकार के औषध विभाग ने एक आदेश पारित कर कार्डियक स्टेण्टस को आवश्यक दवा सूचि में शामिल कर लिया है।

इस आदेश के पारित होने के बाद अब प्रत्येक स्टेण्टस बनाने वाली कम्पनी को उसका अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित करना होगा। अभी तक अधिकतम मूल्य अंकित नही होने से चिकित्सालय में स्टेण्ट का मनमाना मूल्य रोगी से ले लेते थे। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में एक स्टेण्टस का मूल्य 20000/–रू. निश्चित है किन्तु निजी चिकित्सालय रोगियों से 80,000/–रू से 1,25,000/–रू. तक वसूल कर लेते रहे है। सरकार ने विदेशों में निर्मित और भारत में निर्मित स्टेण्टस को समान सूचि में रखा है जिससे चिकित्सकों द्वारा विदेश में निर्मित स्टेण्ट को बेहतर बताकर अधिक राशि वसूल की जाती है पर रोक लगेगी। इससे अनेक हृदय रोगी जो धनाभाव में उपचार से वंचित रह जाते थे के लिए उपचार सम्भव होगा और चिकित्सकों द्वारा व्यर्थ में लगाये जाने वाले स्टेण्टस कि प्रथा पर रोक लगेगी।

सेवानिवृत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जवाहर लाल गार्गिया ने स्वास्थ्य सेवाओं की समस्त नागरिकों की पंहुच के लिए स्वयं सेवी संगठनों का सहयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की कई स्वास्थ्य की योजनाएं है किन्तु जानकारी के अभाव में रोगियों को इसका पूरा लाभ प्राप्त नही हो पाता है। स्वयं सेवी संगठन समुदाय को जागरूक कर योजनाओं की सफल क्रियान्विति के लिए सहयोग प्रदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में सभी सेवा प्रदाताओं में से कुछ अच्छे भी होते है। ग्रामीण क्षेत्र में दुर्घटना होने पर रेफर कर दिया जाता है, पूरी चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है।

जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रामलाल चौधरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा की बात करें तो चिकित्सक शहरों में या नजदीक रहना चाहते है गांवों में जाना ही नहीं चाहते इसलिये ग्राम की चिकित्सा सेवा में सुधार होना चाहिये, विद्यालयों में स्वास्थ्य सुधार कितना आ रहा है इसका मूल्यांकन करना होगा। गांवो की जर–जर सडके भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं में रोडा बनी हुई। अच्छी सडक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही गांवों का विकास संभव है। उन्होंने कई अतिकुपोषित बच्चों का एम्स दिल्ली में उपचार करवाया और निरन्तर ऐसे बच्चों को वहां के उपचार के लिए प्रेरित करने का पुरजोर प्रयास करते है। डॉ. चौधरी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सफल कार्यक्रम आयोजित करवाये है। विद्यालयों में स्वास्थ्य जांच एवं आयरन फोलिक एसिड की गोलिया वितरण कर इसके परिणामों पर निगरानी एवं व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे है।

कार्यक्रम प्रभारी रामेश्वर शर्मा ने मातृत्व प्रजनन एवं स्वास्थ्य अधिकार–स्वास्थ्य सेवाओं की नकारता व अधिकारों का हनन पर 2015 में राज्य से 20 प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश किये गये है। इन में से नसबंदी असफल होने के कारण 10 व्यक्तियों को 30–30 हजार रूपये का लाभ मिल गया है तथा 3 प्रकरणों और निस्तारण हो गया है उनको भी पैसा देने के लिए माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा आदेश जारी हुए है। सेवा के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार है जो कि बिना किसी डिग्री के ग्रामीणों लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है और उन लोगों को वहां से हटाने के लिए कोई रीति नीति नहीं है।

वरिष्ठ समाज सेवी श्री डी एल त्रिपाटी ने कहा कि हम बिमार ही ना हो इस बारे में विचार करना चाहिये। समुदाय को जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होने कहा कि सेवा प्रदाताओं का भी समय–समय पर ओरियेण्टेशन किया जाना चाहिये ताकि योजनाओं का संचालन सही हो सके। इससे यह फर्क आयेगा कि चिकित्सकों द्वारा जो दवायें बाहर की लिखी जा रही है उसमें कमी आयेगी व लोगों को फायदा मिलेगा। लोगों को पूरा पोषण मिलना चाहिये सभी का सर्वांगिण विकास होना चाहिये। कम्यूनिटी मोनिटरिंग को मजबूत बनाना हैं। निशुल्क दवा एवं जांच योजना लागु करवाने में प्रयास ने कई प्रयास किये है तथा अभि भी यह योजना पूरे देश में लागु करवाने के लिए प्रयासरत है। गरीबी का दूसरा महत्वपूर्ण कारण दवाईयों पर खर्च है। उन्होंने चिकित्सालयों में निशुल्क दवाओं की उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए सेवा प्रदाताओं से सहयोग की अपेक्षा की। उन्होने दवाओं के मूल्य निर्धारित करने की मांग को मजबूती से रखने पर जोर दिया और कहा कि इससे दवा कम्पनियों के 4 गुणा मुनाफे में कमी होने के साथ ही उपभोक्ता को उचित मूल्य में दवाइयां उपलब्ध होगी। राजस्थान ईंट भट्टा मजदूर यूनियन के महादेव रेगर, दिनेश यादव, उदयलाल मेघवाल ने संदर्भ सेवाएं प्रदान की। बैठक मे यह भी निर्णय लिया गया कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढीकरण के लिए जनसंवाद का आयोजन किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यक मांग के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदया राजस्थान के नाम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम प्रभारी रामेश्वर शर्मा प्रयास ने किया।

सादर प्रकाशनार्थ !

(कार्यक्रम प्रभारी)